

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 18, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 अक्टूबर 2022

क्रमांक ई 1-06/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2020 बैच के निम्नलिखित परीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में फेस-दो प्रशिक्षण संपन्न करने तथा भारत सरकार में पदस्थापना अवधि समाप्त होने के पश्चात् उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित पद पर पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अभिषेक कुमार	सहायक कलेक्टर, रायपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री हेमंत रमेश नंदनवार	सहायक कलेक्टर, दुर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरायपाली, जिला-महासमुंद.
3.	श्री कुमार बिश्वरंजन	सहायक कलेक्टर, बिलासपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा.
4.	श्री प्रतीक जैन	सहायक कलेक्टर, रायगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर.
5.	सुश्री सुरुचि सिंह	सहायक कलेक्टर, बस्तर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा, जिला-बेमेतरा.
6.	सुश्री रोमा श्रीवास्तव	सहायक कलेक्टर, जांजगीर-चांपा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.
7.	सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो	सहायक कलेक्टर, राजनांदागांव	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली, जिला-मुंगेली.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 नवम्बर 2022

क्रमांक एफ 4-07/सं./30/2021.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश जिसके द्वारा राज्य की कला एवं सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के रामायण मंडलियों के कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत् विकास हेतु “रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना 2021” के अंतर्गत कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/सम्मान/पुरस्कार हेतु बनाये गये नियम में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

नियम के कंडिका क्रमांक — 6,

क्र. (1)	स्तर का नाम (2)	विवरण (3)	प्रोत्साहन राशि (4)	संशोधन प्रोत्साहन राशि (5)
2	ब्लॉक स्तर (146)	प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान में चयनित पंजीकृत रामायण मंडली को प्रोत्साहन राशि	प्रथम-10,000	प्रथम—5000 द्वितीय—3000 तृतीय—2000
3	जिला स्तर (33)	प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान में चयनित पंजीकृत रामायण मंडली को प्रोत्साहन राशि	प्रथम-50,000	प्रथम—25000 द्वितीय—15000 तृतीय—10000

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुसुम एक्का, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2022

क्रमांक/एफ 19-01/2021/25-1.—विभागीय अधिसूचना दिनांक 06-08-2021 द्वारा छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन किया गया है, में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार “बोर्ड का संचालक मंडल” में अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर नामांकित करता है :—

क्रमांक (1)	नामांकित व्यक्ति (2)	पद (3)	गृह जिला (4)
1	श्री तरूण बिजौर	अध्यक्ष	दुर्ग
1	श्री खिलावन बघेल	सदस्य	महासमुन्द
2	श्री किशोर कन्नौजे		दुर्ग
3	सरोजनी रात्रे		गरियाबंद
4	श्री तुलसी दौड़िया		रायपुर

2. उक्त आदेश जारी दिनांक से मानी जावेंगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2022

क्रमांक/एफ 19-02/2022/25-1.—विभागीय अधिसूचना दिनांक 06-08-2021 द्वारा छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन किया गया है, में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार “बोर्ड का संचालक मंडल” में अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर नामांकित करता है :—

क्रमांक (1)	नामांकित व्यक्ति (2)	पद (3)	गृह जिला (4)
1	श्री लोचन विश्वकर्मा	अध्यक्ष	दुर्ग
1	श्री विष्णु विश्वकर्मा	सदस्य	जांजगीर-चांपा
2	श्री शंकरलाल विश्वकर्मा		बस्तर
3	श्री गोविंदराम विश्वकर्मा		सरगुजा
4	श्री धनीराम विश्वकर्मा		रायपुर

2. उक्त आदेश जारी दिनांक से मानी जावेंगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2022

क्रमांक/एफ 19-04/2020/25-1.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 अध्याय-2 की कंडिका 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर, राज्य शासन के प्रसाद पर्यन्त नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	नामांकित व्यक्ति (2)	पद (3)	गृह जिला (4)
1	श्री के. पी. खाण्डे	अध्यक्ष	रायपुर
1	श्री राम पप्पु बघेल	सदस्य	जांजगीर-चांपा
2	श्री बी. एस. जागृत		रायपुर
3	श्री संतोष सारथी		सूरजपुर
4	श्री रमेश पेगवार		जांजगीर-चांपा

2. उक्त आदेश जारी दिनांक से मानी जावेंगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2022

क्रमांक/एफ 19-08/2021/25-1.—विभागीय अधिसूचना दिनांक 06-08-2021 द्वारा छ.ग. रजक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार “बोर्ड का संचालक मंडल” में अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर नामांकित करता है :—

क्र. (1)	बोर्ड का नाम (2)	पद (3)	नामांकित सदस्य का नाम (4)	जिला (5)
15	छ.ग. रजक कल्याण बोर्ड	अध्यक्ष सदस्य	श्री लोकेश कन्नौजे श्री दुखवा राम निर्मलकर श्री भुनेश्वर निर्मलकर श्री राजेन्द्र रजक श्री लक्ष्मीकांत निर्णेजक	बलौदाबाजार मुंगेली कबीरधाम दुर्ग बिलासपुर

2. उक्त आदेश जारी दिनांक से मानी जावेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2022

क्रमांक/एफ 19-08/2021/25-1.—विभागीय अधिसूचना दिनांक 06-08-2021 द्वारा तेलघानी बोर्ड का गठन किया गया है, में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार “बोर्ड का संचालक मंडल” में सदस्य पद पर नामांकित करता है :—

क्र. (1)	बोर्ड का नाम (2)	पद (3)	नामांकित सदस्य का नाम (4)	जिला (5)
4.	तेलघानी बोर्ड	सदस्य	1. शैलेन्द्र साहू 2. श्री लक्ष्मी गुप्ता 3. श्री रोहित साहू	गरियाबंद सरगुजा बलौदाबाजार

2. उक्त आदेश जारी दिनांक से मानी जावेगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2022

क्रमांक आर 1235/2022/25-1.—विभागीय अधिसूचना दिनांक 29-09-2007 द्वारा अंत्यावसायी निगम का गठन किया गया है, में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार “संचालक मंडल” में सदस्य पद पर नामांकित करता है :—

क्र. (1)	बोर्ड का नाम (2)	पद (3)	नामांकित सदस्य का नाम (4)	जिला (5)
3	छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित	सदस्य	श्री वेदराम मनहरे के स्थान पर श्री निलेश बंजारे	बलौदाबाजार

2. उक्त आदेश जारी दिनांक से मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एमरेंसिया खेस्स, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 नवम्बर 2022

क्रमांक 12413/3286/21-ब(एक)/छ.ग./2022.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा रिट अपील क्रमांक 281/2022 उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ विरुद्ध गणेश राम बर्मन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29-07-2022 एवं रिट पिटिशन (एस) क्रमांक 825/2017 गणेश राम बर्मन विरुद्ध उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13-05-2022 तथा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1179/दो-2-1/2022/गोप./2022 दिनांक 17-10-2022 के पालन में, इस विभाग द्वारा श्री गणेश राम बर्मन को सेवा से बर्खास्त (terminate) करने के संबंध में, जारी आदेश क्रमांक 1296/276/21-ब/छ.ग./2017 दिनांक 06-02-2017 को निरस्त करते हुए, श्री गणेश राम बर्मन, सदस्य उच्चतर न्यायिक सेवा को तत्काल प्रभाव से अर्थात् उनके सेवा में कार्यभार पुनः ग्रहण करने के दिनांक से बकाया वेतन को छोड़कर सेवा के समस्त परिणामी स्वत्वों के साथ सेवा में बहाल (reinstated in service forth-with along with all consequential service benefits except back-wages) करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 नवम्बर 2022

क्रमांक 12305/3116/21-ब/2022.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पास्टर श्री जी. एन. कुलदीप, क्रिश्चियन चर्च, लोरमी को, छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु, अनुज्ञप्ति मंजूर करता है।

No. 12305/3116/21-B/2022.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government, is hereby, pleased to grant license to (Minister of Religion) Paster Shri G.N. Kuldeep, Christian Church Lormi, for District Mungeli of Chhattisgarh State :—

1. to Solemnize Marriage; and
2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 नवम्बर 2022

शुद्धि-पत्र

क्रमांक 12481/डी-107/21-अ/छ.ग./22.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 में यथा प्रकाशित छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्र. 17 सन् 2022) के अंग्रेजी पाठ में, पृष्ठ क्रमांक 1218(8) में, टीप के सरल क्रमांक 5 में, अंक एवं शब्द “12 percent”, को “14 percent” पढ़ा जाये।

No. 12481/D-107/XXI-A/C.G./22.— In the Chhattisgarh Electricity Duty (Amendment) Act, 2022 No. 17 of 2022) as published in the Chhattisgarh Gazette, Extra-ordinary, dated 11th October 2022, in English version, at page 1218(8), in serial number 5 of Note, for the figure and word “12 percent”, read “14 percent”.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 नवम्बर 2022

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. का पत्र क्रमांक 439/स्था./वि.स.उप नि./2022/3522 के साथ भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या ECI/PN/83/2022 दिनांक 05-11-2022 के अनुसार विधानसभा उप निर्वाचन-2022 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। जिसके अनुसार विधानसभा उप निर्वाचन-2022 हेतु मतदान दिनांक 05-12-2022 को निर्धारित है।

2. मतदान दिवस के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दिया जाना है एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपरोक्त प्रावधान में मतदान दिवस को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के निर्देश हैं, चूंकि औद्योगिक उपक्रमों, निजी उपक्रमों एवं अन्य व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारी/श्रमिक उपरोक्त प्रावधान की परिधि में आते हैं, अतः अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के लिये विभाग/जिले में चल रहे सभी औद्योगिक उपक्रमों, निजी उपक्रमों एवं अन्य व्यवसायों से इस प्रावधान का पालन सुनिश्चित कराया जाना है, चूंकि विधानसभा उप निर्वाचन-2022 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80-भानुप्रतापपुर हेतु मतदान दिनांक 05-12-2022 (सोमवार) को निर्धारित है।

3. अतः लोक प्रतिनिधित्व, 1951 की धारा 135 ख-“मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी” लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख में निम्नानुसार प्रावधान है :—

- (i) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
- (ii) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे दिन के लिए वह मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती।
- (iii) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
- (iv) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपरोक्त प्रावधान में मतदान दिवस को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के निर्देश है।

5. अतएव राज्य शासन एतद्वारा कार्या. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र दिनांक 05-11-2022 के अनुक्रम में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक/कर्मचारियों को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80-भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) हेतु मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिता गुप्ता, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मोहला मानपुर अं. चौकी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मोहला-मानपुर-अं. चौकी, दिनांक 20 अक्टूबर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/922/भू-अर्जन/2022.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/कृषकों की संख्या	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मोहला-मानपुर-अं. चौकी	अं. चौकी	दोड़के प.ह.नं. 22/कृषकों की संख्या 03	0.466 हे.	लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग दुर्ग के अंतर्गत शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 09-12-2022 को समय 11.00 AM से 3.00 PM बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन दोड़के पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग दुर्ग के अंतर्गत शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	03
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन में सुविधा
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. जयवर्धन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

कोरबा, दिनांक 16 नवम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/13772/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	दर्दी	भैरोताल	0.259 हे.	कटघोरा-हरदीबाजार-बलौदा-अकलतरा मार्ग में खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल के पहुँच मार्ग का निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 07-12-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान सामुदायिक भवन भैरोताल प्रेमनगर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | कटघोरा-हरदीबाजार-बलौदा-अकलतरा मार्ग में खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल के पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य. |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 07 परिवार |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | निरंक |
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—
की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 5. | प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार
कर लिया गया है. | — | हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — | रुपये 1496.09 लाख |
| 9. | परियोजना से होने वाला लाभ | — | परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे
आस-पास के 11 ग्रामों के लगभग 265703 ग्रामवासी
लाभांविता होंगे. |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये
संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु 5 प्रतिशत सर्विस
चार्ज की राशि रुपये 14196.00 डी.डी. 607012 दिनांक
29-04-2022 के माध्यम से कार्यालय अनुविभागीय
अधिकारी कटघोरा (रा.) जिला कोरबा (छ.ग.) को
भुगतान किया गया है. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 16 नवम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/13782/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	कुचेना	0.494 हे.	कटघोरा-हरदीबाजार-बलौदा-अकलतरा मार्ग में खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल के पहुँच मार्ग का निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 08-12-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान सामुदायिक भवन कुचेना नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण | — | कटघोरा-हरदीबाजार-बलौदा-अकलतरा मार्ग में खोलार नाला पर उच्चस्तरीय पुल के पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य. |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | 09 परिवार |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | निरंक |
| 4. | प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों—की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 5. | प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. | — | निरंक |
| 6. | क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? | — | हां |
| 7. | क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है. | — | हां |
| 8. | परियोजना की कुल लागत | — | रुपये 1496.09 लाख |
| 9. | परियोजना से होने वाला लाभ | — | परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 11 ग्रामों के लगभग 265703 ग्रामवासी लाभांविता होंगे. |
| 10. | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. | — | प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु 5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की राशि रुपये 29270.00 डी.डी. क्रमांक 652352 दिनांक 25-05-2022 के माध्यम से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा (रा.) जिला कोरबा (छ.ग.) को भुगतान किया गया है. |
| 11. | परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक | — | निरंक |

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 नवम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/13919/क/भू-अर्जन/202010050400004/अ-82/2020-21.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	उरगा	0.069 हे.	चाम्पा-गेवरा रेलमार्ग (उरगा के पास) रेल्वे ओव्हर ब्रिज के पहुंच मार्ग का निर्माण.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21-12-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम उरगा नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	चाम्पा-गेवरा रेलमार्ग (उरगा के पास) रेल्वे ओव्हर ब्रिज के पहुंच मार्ग निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	2828.00 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन की सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 18 नवम्बर 2022

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/13923/क/भू-अर्जन/202202050400001/अ-82/2021-22.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	अजगरबहार	कोड़ियाघाट	1.393 हे.	झोरा-कोड़ियाघाट मार्ग में हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल के पहुंच मार्ग निर्माण.

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17-12-2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम कोड़ियाघाट नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	झोरा-कोड़ियाघाट में हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल के पहुंच मार्ग निर्माण.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	17
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	1915.19 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन की सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2020-21.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण सेतु संभाग रायगढ़ द्वारा ग्राम-छींच, प.ह.नं.-27 तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 0.659 हे. लंकापाली-छींच मार्ग के लालडीपा नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11(1) की अधिसूचना तथा धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 06-08-2021 तथा दिनांक 21-01-2022 को कराया गया है।

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण सेतु संभाग रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि पुल में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है।

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-छींच		
क्र.	ख.नं.	रकबा
1.	253/1	0.010
कुल खसरा - 01 कुल रकबा 0.010		

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202204041800004/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	राजपुर प.ह.नं.-03	1.488	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर.	बकारूमा-लैलूंगा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य भू-अर्जन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

रायगढ़, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202204041800009/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	हीरापुर प.ह.नं.-36	0.068	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर.	बकारूमा-लैलूंगा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य भू-अर्जन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202204041800010/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	बगुडेगा प.ह.नं.-01	2.799	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर.	बकारूमा-लैलूंगा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य भू-अर्जन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202204041800014/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	सराईमुडा प.ह.नं.-02	0.624	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर.	बकारूमा-लैलूंगा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य भू-अर्जन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202204041800015/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	सलखिया प.ह.नं.-13	0.986	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर.	बकारूमा-लैलूंगा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य भू-अर्जन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202204041800016/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	झरन प.ह.नं.-12	0.390	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर.	बकारूमा-लैलूंगा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य भू-अर्जन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202204041800017/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	धियारमुडा प.ह.नं.-13	0.100	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर.	बकारूमा-लैलूंगा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य भू-अर्जन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202204041800018/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	खम्हार प.ह.नं.-11	0.580	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर.	बकारूमा-लैलूंगा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य भू-अर्जन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202204041800018/अ-82/2022.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	चौरंगा प.ह.नं.-02	0.955	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर.	बकारूमा-लैलूंगा मार्ग का उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य भू-अर्जन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा, जिला-रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2021-22.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ टाउन प.ह.नं. 56	0.378	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.).	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2022

क्रमांक/09/अ-82/2021-22.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- जिला-बिलासपुर
 - तहसील-तखतपुर
 - नगर/ग्राम-अरईबंद
 - लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर

खसरा नम्बर
(1)
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

799/1 में से 0.121
799/2 में से 0.040

योग 02 0.161

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अरपा भैंसाझार
बैराज परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), तखतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2022

क्रमांक/10/अ-82/2021-22.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		4 में से	0.057
(क) जिला-बिलासपुर			
(ख) तहसील-तखतपुर		580/1 में से	0.053
(ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.246 हेक्टेयर			
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	योग	
(1)	(2)	03	0.199
693	0.097		
667/2	0.105		
792/1	0.028		
47/2	0.016		
योग	04		0.246

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तखतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2022

क्रमांक/11/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन-	
(क) जिला-बिलासपुर	
(ख) तहसील-तखतपुर	
(ग) नगर/ग्राम-मोछ	
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.199 हेक्टेयर	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3/1 में से	0.089

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन-	
(क) जिला-रायगढ़	
(ख) तहसील-रायगढ़	
(ग) नगर/ग्राम-साल्हेओना	
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24/6	0.008

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2022

प्रकरण क्रमांक 202112042100011/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन-	
(क) जिला-रायगढ़	
(ख) तहसील-रायगढ़	
(ग) नगर/ग्राम-साल्हेओना	
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24/6	0.008

(1)	(2)
25/1	0.004
25/3	0.016
योग	03
	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—साल्हेओना-कुकुर्दा मार्ग के सपनई नाला पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1401/202112042900042/अ-82/2021-22.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-नावापारा (पं.)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.1459 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127	0.030
123/3क	0.0216
126	0.0368
87/1ग	0.0104
123/5क	0.0255
123/4	0.0216
योग	6
	0.1459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नावापारा-भाटपारा मार्ग के माकाखड़िया नाला पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया, जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1402/202107042900077/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तिऊर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.332 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
388/1	0.081
399/1	0.081
388/3	0.081
395	0.040
396/3	0.049

योग 5 0.332

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—तुरेकेला तिऊर मार्ग के सपनाई नाला पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया, जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2022

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1403/202107042900078/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-तुरेकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.407 हेक्टेयर

(1)

(2)

478

0.389

477

0.018

योग

2

0.407

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तुरेकेला तिकुर मार्ग के सपनाई नाला पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया, जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानू साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 4 नवम्बर 2022

क्रमांक/8975/कले./भू-अर्जन/भूकनी/2022.—एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के तहत कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग द्वारा निर्माणाधीन मासाभाट जलाशय नहर निर्माण कार्य के लिये ग्राम भिलाई प.ह.नं. 07 तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद के निम्नानुसार भू-धारकों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है :-

क्र.	भू-धारकों का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में)	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री बुधराम पिता हरलाल जाति यादव निवासी ग्राम भिलाई, प.ह.नं. 07 तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद	153/1	0.850	0.08
2.	श्री भारत, भीषम, छबीलता पिता रिखीराम, रेणुबाई बेवा, रिखीराम जाति तेली निवासी भिलाई	647/3	0.81	0.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	सुरजा बाई पिता तेजराम	559	0.630	0.04
	जाति कुर्मी निवासी ग्राम भिलाई	552	0.130	0.05
		534	0.340	0.01
		532	0.550	0.05
योग		06	3.31	0.37

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में किसी को कोई आपत्ति हो, तो 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अधिकृत अधिकर्ता के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

कुलदीप शर्मा,
कलेक्टर.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 16 नवम्बर 2022

पुनर्गठित बालोद निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्रमांक/1044/पुन.बालोद नि.क्षे./नग्रानि/2022.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पुनर्गठित बालोद निवेश क्षेत्र के ग्राम-झलमला, पाकुरभाट, देवारभाट, उमरादाह के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति :—

1. कार्यालय संभागीय आयुक्त दुर्ग, संभाग दुर्ग (छ.ग.)
2. कलेक्टोरेट, जिला कलेक्टर, बालोद (छ.ग.)
3. कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद (छ.ग.)
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद् बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान जनसामान्य निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव, इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद (छ.ग.) में छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद (छ.ग.) द्वारा विचार किया जायेगा.

Notice inviting objections to existing land use map of Reconstituted Balod Planning Area

No./1044/Rec.Balod P.A./T&CP/2022.—Notice is hereby given that the existing land use map of village jhalmala, pakurbhat, dewarbhat, umaradah for Reconstituted Balod planning area has been prepared under the sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of thereof is available for inspection during office hours in the offices of :—

1. Office of the Divisional Commissioner, Durg Division (C.G.)
2. Collectorate, District Collector, Balod (C.G.)
3. Office of the Assistant Director, Town And Country Planning Regional Office Balod (C.G.)
4. Office of the Nagar Palika Parishad Balod, District Balod (C.G.)

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it shall be submitted in writing to the office of the Assistant Director, Town and Country Planning Balod (C.G.) within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette for due consideration, will be considered by the Assistant Director Town and Country Planning Balod (C.G.).

प्रतीक दीक्षित,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th November 2022

No. 14034/Rules/2022.—In exercise of the powers conferred under Articles & 225 and 227 of the Constitution of India, the High Court, of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the High Court of Chhattisgarh Rules, 2007, which shall come into force with immediate effect :—

AMENDMENTS

“Proforma of Non-Bailable Warrant for production of acquitted person/respondent and of Bailable Warrant for production of acquitted person/respondent be inserted as Form-18 and Form-19 in the Schedule-A of High Court of Chhattisgarh Rules, 2007.”

FORM No. 18

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

(NON-BAILABLE WARRANT FOR PRODUCTION OF ACQUITTED PERSON/RESPONDENT)

ACQUITTAL APPEAL NO.

FIXED FOR at 10.30 A.M.

To,

THE SUPERINTENDENT OF POLICE,
DISTRICT (C.G.)

WHEREAS the Acquittal appeal has been filed by the Applicant/Complainant
S/o against the order/judgment date..... passed by
the (C.G.) in S.T. No. which was registered as
Acquittal Appeal No.

No representation has been made on behalf of the acquitted person/respondent
S/o, in the Hon'ble Court on

WHEREAS this Court has directed in Acquittal Appeal No. that
the acquitted person/respondent S/o
aged about years, R/o District (C.G.)
be produced before this Court on at 10.30 AM.

You are hereby required to arrest and produce the said Acquitted person/respondent
S/o before the C.J.M. to take action u/s
390 Cr. P.C. by committing him to prison and directing the Jail Authority to produce him before the Hon'ble High
Court on at 10.30 AM as per direction of Hon'ble High Court.

Given under my hand and the seal of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur (C.G.) this
day of

Encl : Copy of order dated

BY ORDER OF THE HIGH COURT

(.....)

Additional Registrar (Judicial)

Endt. No. /Acq. A. No.

Bilaspur, dated

Copy forwarded to the,(C.G.) for information and
necessary action.

Encl : Copy of order dated

(.....)

Additional Registrar (Judicial)

FORM No. 19

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR
(BAILABLE WARRANT FOR PRODUCTION OF ACQUITTED PERSON/RESPONDENT)

ACQUITTAL APPEAL NO.

FIXED FOR at 10.30 A.M.

To,

THE SUPERINTENDENT OF POLICE,
DISTRICT (C.G.)

WHEREAS the Acquittal appeal has been filed by the Applicant/Complainant
S/o against the order/judgment date..... passed by
the (C.G.) in S.T. No. which was registered as
Acquittal Appeal No.

No representation has been made on behalf of the acquitted person/respondent
S/o, in the Hon'ble Court on

WHEREAS this Court has directed that the acquitted person/respondent
S/o aged about years, R/o
District (C.G.) be produced before this Court on at 10.30 AM.

You are hereby required to arrest and produce the said Acquitted person/respondent
S/o before the C.J.M. to take action
u/s 390 Cr. P.C.

If the said acquitted person/respondent S/o
furnishes personal bond in the sum of Rs. and a surety of like amount before the
C.J.M., he shall be released on bail with a direction to appear before Hon'ble the High Court
of Chhattisgarh on at 10.30 AM and to continue so to attend until otherwise directed by this Court.

Given under my hand and the seal of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur (C.G.) thisday
of

Encl : Copy of order dated

BY ORDER OF THE HIGH COURT

(.....)
Additional Registrar (Judicial)

Endt. No. /Acq. A. No.

Bilaspur, dated

Copy forwarded to the Chief Judicial Magistrate, (C.G.) for information and
necessary action.

Encl : Copy of order dated

(.....)
Additional Registrar (Judicial)

By order of Hon'ble the High Court,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.
